



प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

DEPARTMENT OF
ADMINISTRATIVE REFORMS &
PUBLIC GRIEVANCES

75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav



नेस्टा – वे फॉरवर्ड
राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मासिक रिपोर्ट
जनवरी और फरवरी 2024

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

विषयवस्तु

1. परिचय	2
2. मुख्य विशेषताएं	4
3. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा	6
4. एकीकृत सेवा प्रदायगी पोर्टल	11
4.1. परिपूर्णता स्थिति	11
4.2. सर्वोत्तम परिपाटियाँ - एकीकृत सेवा प्रदायगी पोर्टल	13
4.2.1. गोवा ऑनलाइन	14
4.2.2. आपले सरकार	15
4.2.3. छत्तीसगढ़ ई-डिस्ट्रिक्ट	16
4.2.4. मीसेवा	17
4.2.5. अंडमान ई-डिस्ट्रिक्ट	18
4.2.6. सेवा ऑनलाइन	19
5. पूर्वोत्तर राज्यों में ई-सेवा प्रदायगी को सुदृढ़ करना	20
6. सामान्य ई-सेवाएँ	21
7. सेवा प्रदायगी की गुणवत्ता में सुधार	22
8. मीडिया आउटरीच	24
9. परिशिष्ट	27
9.1. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ई-सेवाओं की स्थिति की मासिक प्रगति	27
9.2. अभिचिन्हित सामान्य ई-सेवाओं की सूची	28

1. परिचय

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने सात क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक बेंचमार्किंग प्रयोग के रूप में ई-सेवाओं की प्रदायगी के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केंद्रीय मंत्रालयों का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा प्रदायगी मूल्यांकन (नेस्डा) फ्रेमवर्क तैयार किया। डीएआरपीजी का आशय नेस्डा अध्ययन को द्विवार्षिक रूप से आयोजित करने का है।

नेस्डा 2021 के उत्साहजनक निष्कर्षों के मद्देनजर, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ई सेवा प्रदायगी में मासिक प्रगति की निगरानी के लिए नेस्डा वे फॉरवर्ड पीएमयू की स्थापना की गई। डीएआरपीजी नेस्डा वे फॉरवर्ड मासिक रिपोर्ट और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के एसपीओसी के साथ नियमित समीक्षा बैठकों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ई-सेवा प्रदायगी में हुई प्रगति और एकीकृत सेवा प्रदायगी पोर्टलों में वृद्धि की निगरानी करता है। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ई-सेवा प्रदायगी की स्थिति की निगरानी के लिए 9 नेस्डा वे फॉरवर्ड मासिक रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट 2023 प्रकाशित की गई हैं।

2023 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जारी की गई मासिक रिपोर्ट में विशेष रूप से सात विशेष ध्यान केंद्रण वाले क्षेत्रों अर्थात् पर्यटन (मई), पर्यावरण (जून), शिक्षा (जुलाई), श्रम और रोजगार (अगस्त), वित्त (सितंबर), कृषि, स्वास्थ्य और गृह सुरक्षा सहित समाज कल्याण (अक्टूबर) और स्थानीय शासन और जनोपयोगी सेवाएं (नवंबर) में से प्रत्येक में ई-सेवाओं का गहन विश्लेषण शामिल है।

आगामी मासिक का लक्ष्य ई-सेवाओं की बेहतर प्रदायगी के लिए देश के प्रयासों को संस्थागत बनाना और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को द्विवार्षिक नेस्डा के लिए तैयार करना है।

नेस्डा वे फॉरवर्ड मासिक रिपोर्ट के वर्णित उद्देश्य इस प्रकार हैं:

क. ई-सेवाओं की परिपूर्णता

- सभी अभिचिन्हित 56 अनिवार्य ई-सेवाओं का प्रावधान
- प्रदान की गई ई-सेवाओं की कुल संख्या की प्रदायगी में वृद्धि
- अभिचिन्हित सामान्य सेवाओं का प्रावधान

ख. गोपनीय और स्वतः पात्रता-आधारित सेवा प्रदायगी को बढ़ावा देना

- प्रदान की गई सेवाओं की संख्या में सुधार की निगरानी अर्थात् फिजिकल विजिट, कागजी कार्रवाई और मानवीय हस्तक्षेप के बिना गोपनीय रूप से करना।
- नागरिकों को उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर उनकी पात्रता के अनुसार ई-सेवाएँ प्रदान करना

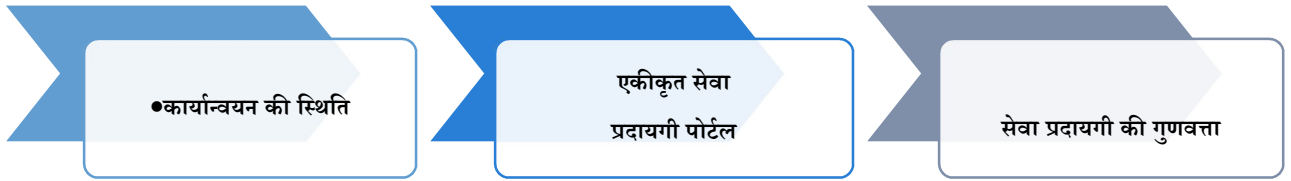
ग. एकीकृत सेवा प्रदायगी पोर्टलों का सुदृढीकरण

- विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में एकीकृत सेवा प्रदायगी पोर्टल को सुदृढ करना ।
- सर्विस प्लस, माईस्कीम, उमंग आदि जैसे अन्य सरकारी प्लेटफार्मों के साथ एकीकरण ।

घ. बाधाओं की पहचान और सर्वोत्तम परिपाटियों का प्रसार

- मौजूदा अंतरालों का पता लगाना और नेस्टा मूल्यांकन मापदंडों में स्कोर में सुधार करना ।
- उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने के लिए सर्वोत्तम परिपाटियों से सीखना ।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए नेस्टा वे फॉरवर्ड मासिक रिपोर्ट, जनवरी और फरवरी 2024, दिनांक 05 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार नेस्टा - वे फॉरवर्ड डैशबोर्ड पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए इनपुट पर आधारित है ।



2. मुख्य बिन्दु

कार्यान्वयन की स्थिति

- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 16,517 ई-सेवाएँ प्रदान की जाती हैं
- तमिलनाडु अधिकतम ई-सेवाएँ प्रदान करता है (1128)
- अधिकतम ई-सेवाएँ (5,288) - स्थानीय शासन और जनोपयोगी सेवा क्षेत्र में हैं
- 2,016 अनिवार्य ई-सेवाओं में से 1,528 (56*36 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र) उपलब्ध हैं, जिससे परिपूर्णता 76% हो गई है
- मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तराखंड ने 56 अनिवार्य ई-सेवाओं में 100% परिपूर्णता हासिल कर ली है

एकीकृत सेवा प्रदायगी पोर्टल

- तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर, केरल, असम और ओडिशा अपनी 100% सेवाएँ अपने अभिचिन्हित एकल एकीकृत सेवा प्रदायगी पोर्टल यानी, क्रमशः लेसेवाई (1128), ई-उन्नत (1119), ई-सेवानम (911), सेवा सेतु (469) और ओडिशा वन (404) के माध्यम से प्रदान करते हैं
- गोवा सरकार ने सभी सरकारी सेवाओं को सामान्य सेवा प्रदायगी आउटलेट के माध्यम से अपने इलाके में आम नागरिक तक पहुंच बनाने के लिए गोवा ऑनलाइन विकसित किया है
- महाराष्ट्र सरकार ने नागरिकों को आरटीएस अधिनियम के तहत उपलब्ध सेवाओं के बारे में जानकारी तक पहुंच प्रदान करने के लिए आरटीएस महाराष्ट्र मोबाइल ऐप या आपले सरकार वेब पोर्टल डिज़ाइन किया है।
- छत्तीसगढ़ सरकार ने ई-डिस्ट्रिक्ट लॉन्च किया है, जो आवेदन, स्थिति जांच, डाउनलोड और संपर्क जानकारी (मोबाइल ऐप उपलब्ध) के लिए सरकारी सेवाओं तक 24/7 पहुंच प्रदान करता है।
- तेलंगाना सरकार ने मी सेवा डिज़ाइन किया है, जो ऑनलाइन, कियोस्क और मोबाइल ऐप एक्सेस के साथ जी2सी और जी2बी सेवाएं प्रदान करता है।
- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सरकार ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) के तहत स्थापित ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना विकसित की, जो जिला और उप-जिला स्तरों पर उच्च मात्रा में नागरिक सेवाएं प्रदान करती है।
- बिहार सरकार ने ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना को डिज़ाइन किया है जिसे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी) द्वारा कुशल सेवा प्रदायगी के लिए सर्विस प्लस फ्रेमवर्क का उपयोग करके निष्पादित किया जाता है।

पूर्वोत्तर राज्यों में ई-सेवा प्रदायगी को सुदृढ़ करना

- डीएआरपीजी ने मणिपुर के एकीकृत सेवा प्रदायगी पोर्टल को सुदृढ़ करने के लिए **मणिपुर सरकार** और **जम्मू-कश्मीर सरकार** के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 19-20 फरवरी, 2024 को 2 दिवसीय बैठकें आयोजित कीं।

सामान्य ई-सेवाएँ

- 9 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी सामान्य ई-सेवाओं को नेस्टा वे फॉरवर्ड डैशबोर्ड पर मैप किया है
- अभिचिह्नित सामान्य ई-सेवाओं की सूची अनुबंध 9.2 में संलग्न है

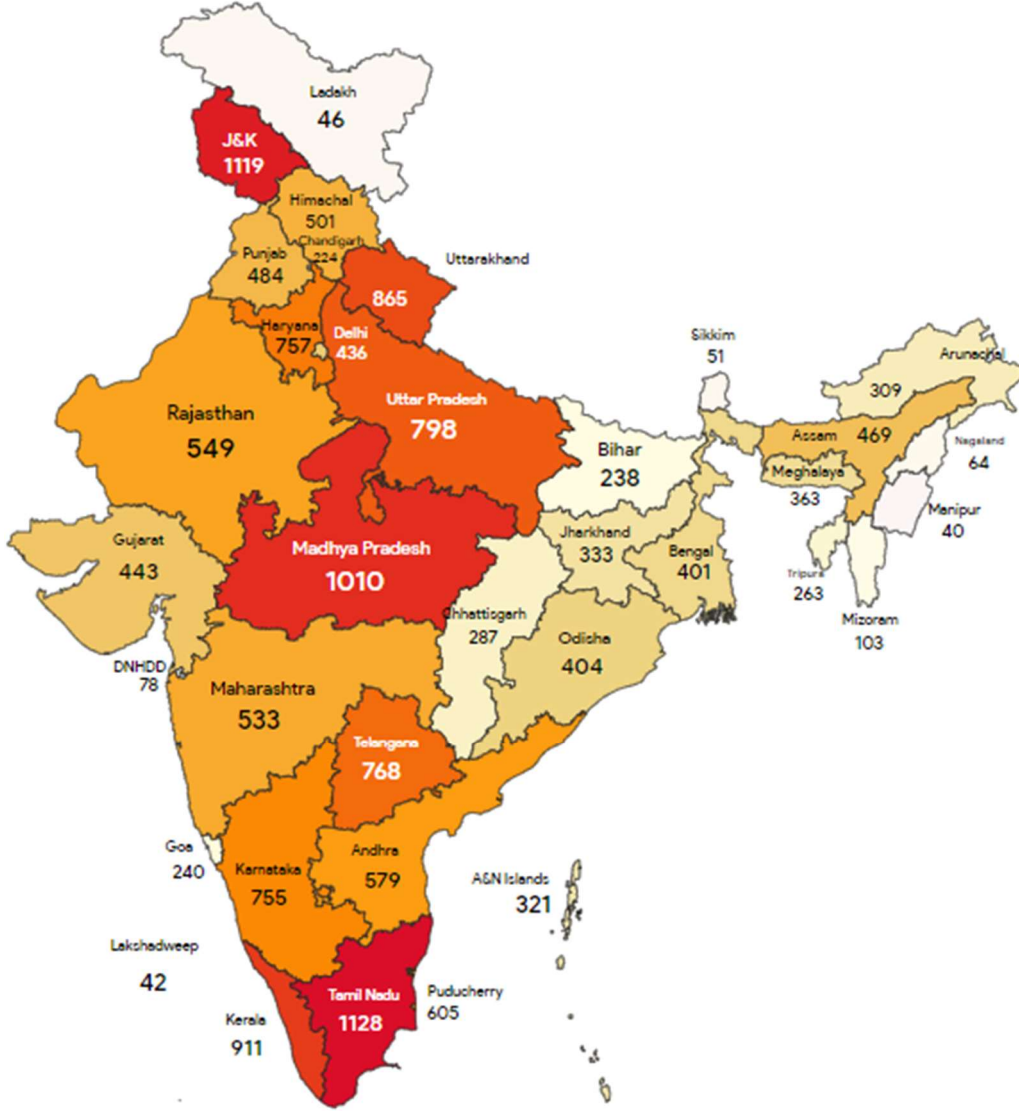
सेवा प्रदायगी की गुणवत्ता में सुधार

- दुनिया भर में समकालीन डिजिटल सरकारी प्रवृत्तियों और नागरिकों की ज़रूरतों के अनुरूप, नेस्टा ढांचे में तीन नए अतिरिक्त मूल्यांकन पैरामीटर, अर्थात् **ओपन सरकारी डेटा**, **ई-भागीदारी** और **उभरती प्रौद्योगिकियों** का लाभ उठाना शामिल किए गए हैं।

3. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा

ई-सेवाओं की स्थिति

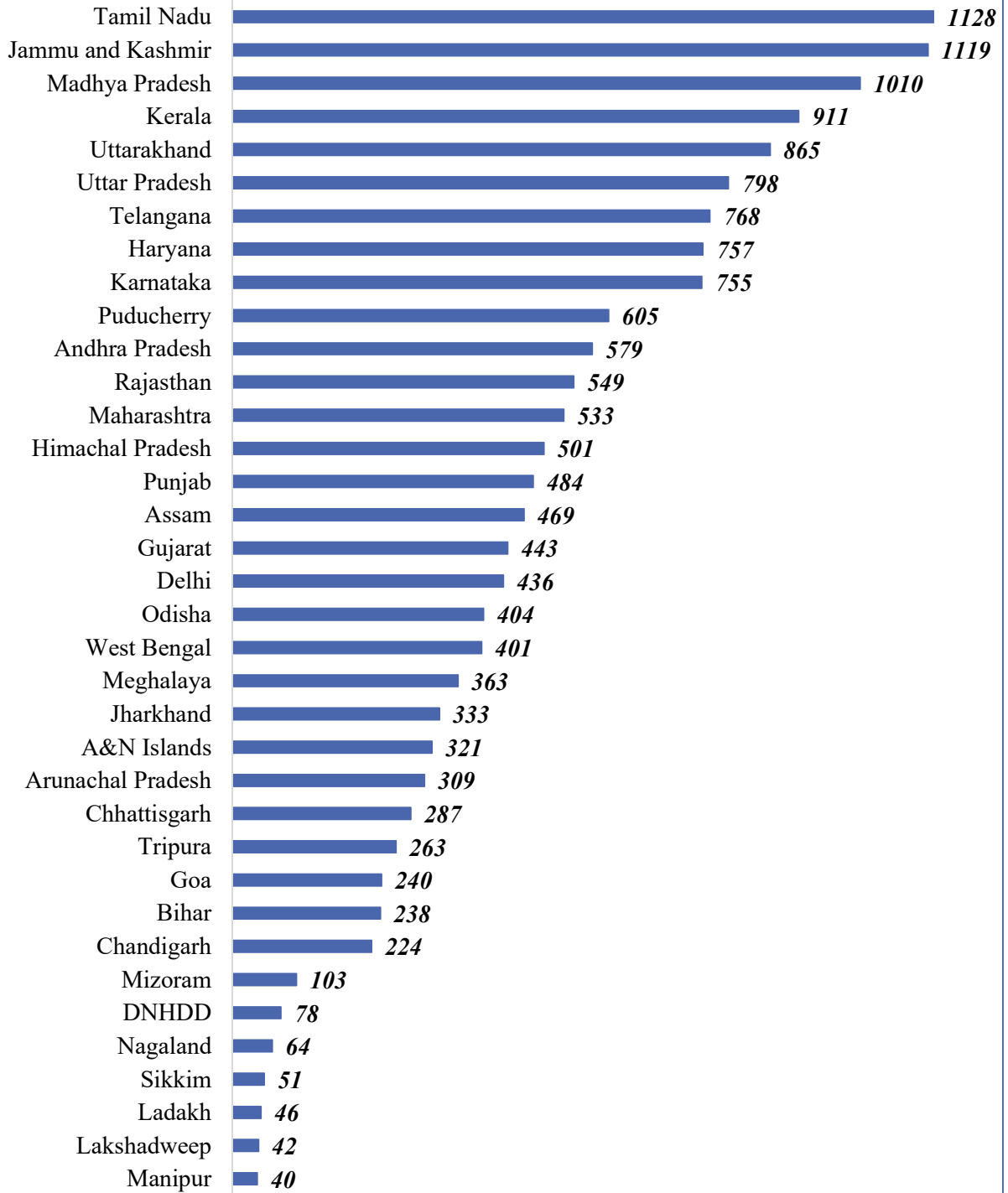
नेस्टा - वे फॉरवर्ड डैशबोर्ड पर इनपुट के अनुसार



कुल ई-सेवाएँ
16,517

नोट: उपरोक्त आंकड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 05/03/2024 तक अपलोड किए गए हैं।

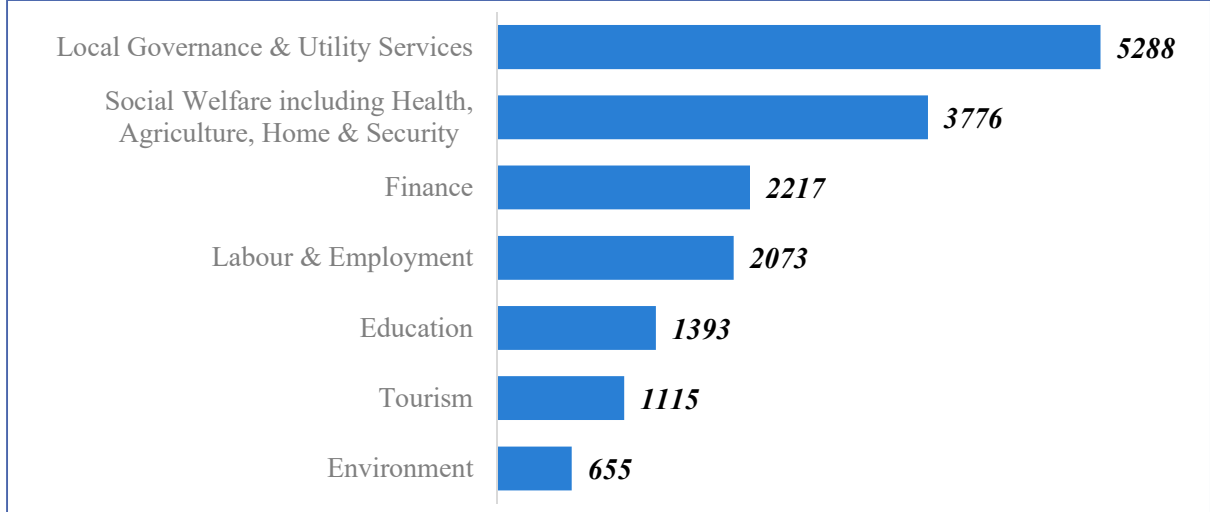
ई-सेवाओं की स्थिति
नेस्टा - वे फॉरवर्ड डैशबोर्ड पर इनपुट के अनुसार



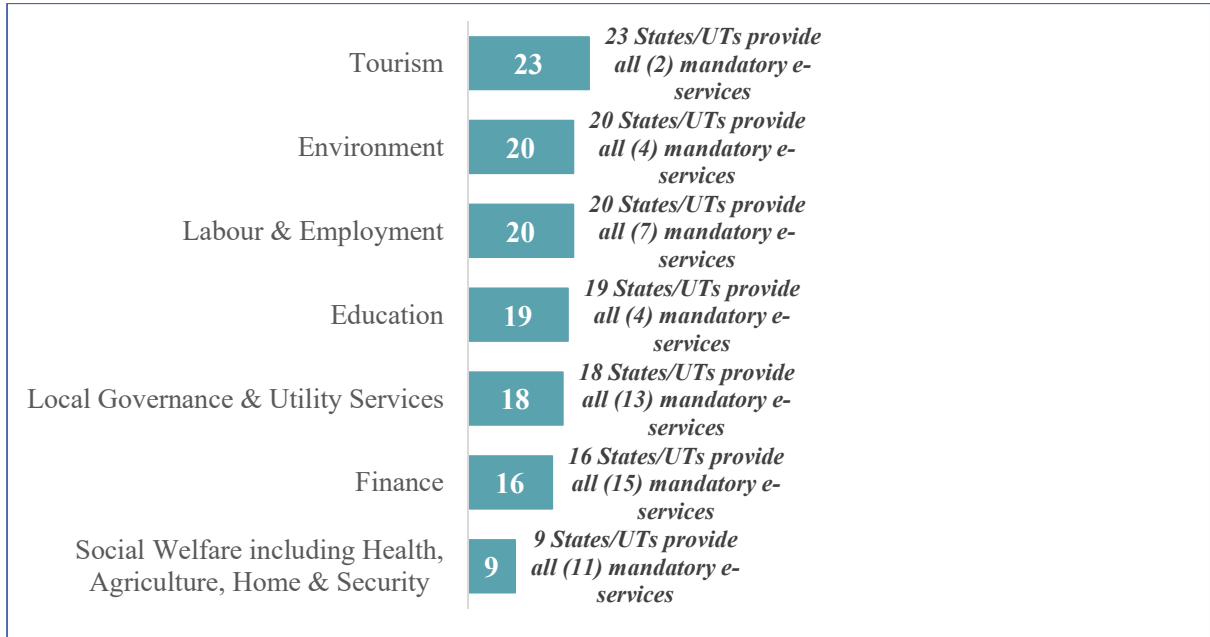
राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ई-सेवाओं की स्थिति की मासिक प्रगति अनुबंध 9.1 में संलग्न है।

नोट: उपरोक्त आंकड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 05/03/2024 तक अपलोड किए गए हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ई-सेवाओं की क्षेत्र-वार समेकित स्थिति

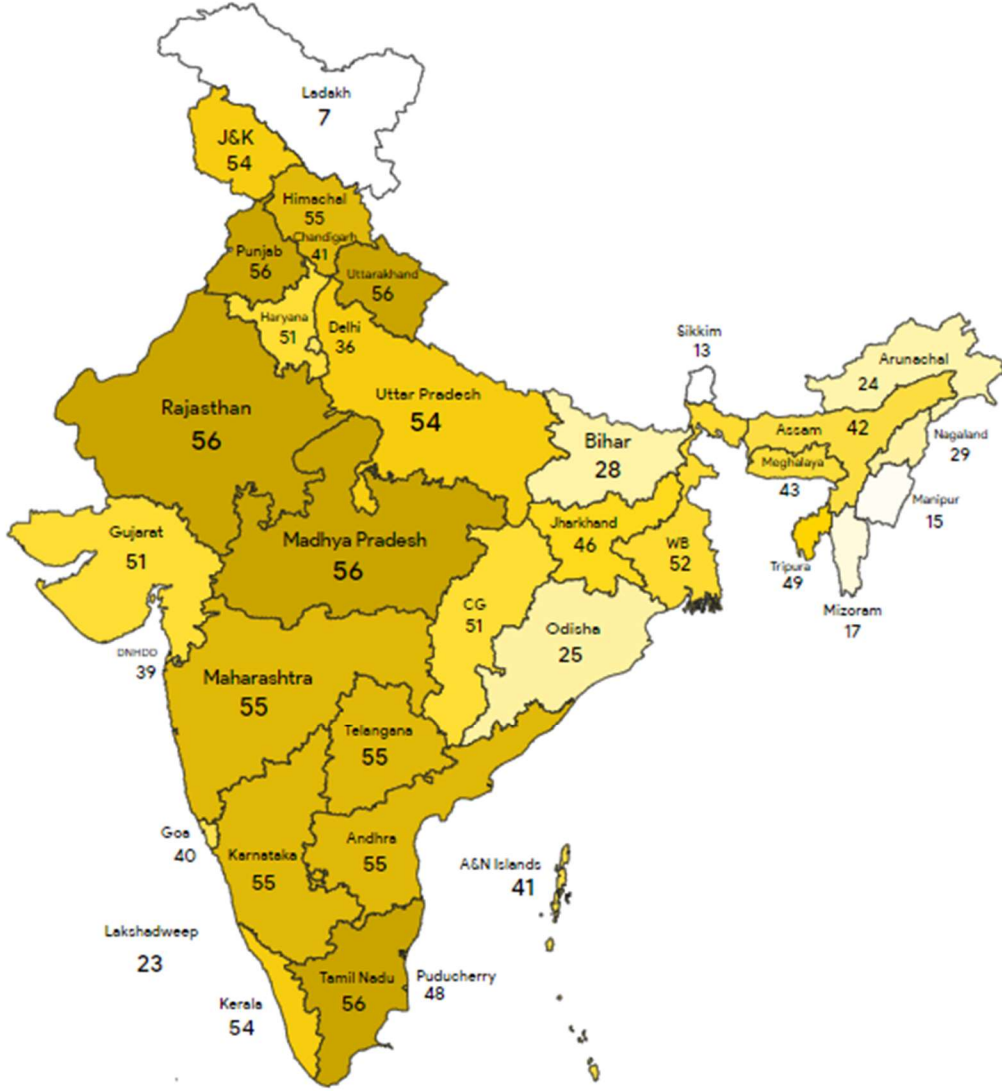


राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनिवार्य ई-सेवाओं की क्षेत्र-वार परिपूर्णता स्थिति



नोट: उपरोक्त आंकड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 05/03/2024 तक अपलोड किए गए हैं।

56 अनिवार्य ई-सेवाओं की स्थिति
नेस्टा - वे फॉरवर्ड डैशबोर्ड पर इनपुट के अनुसार



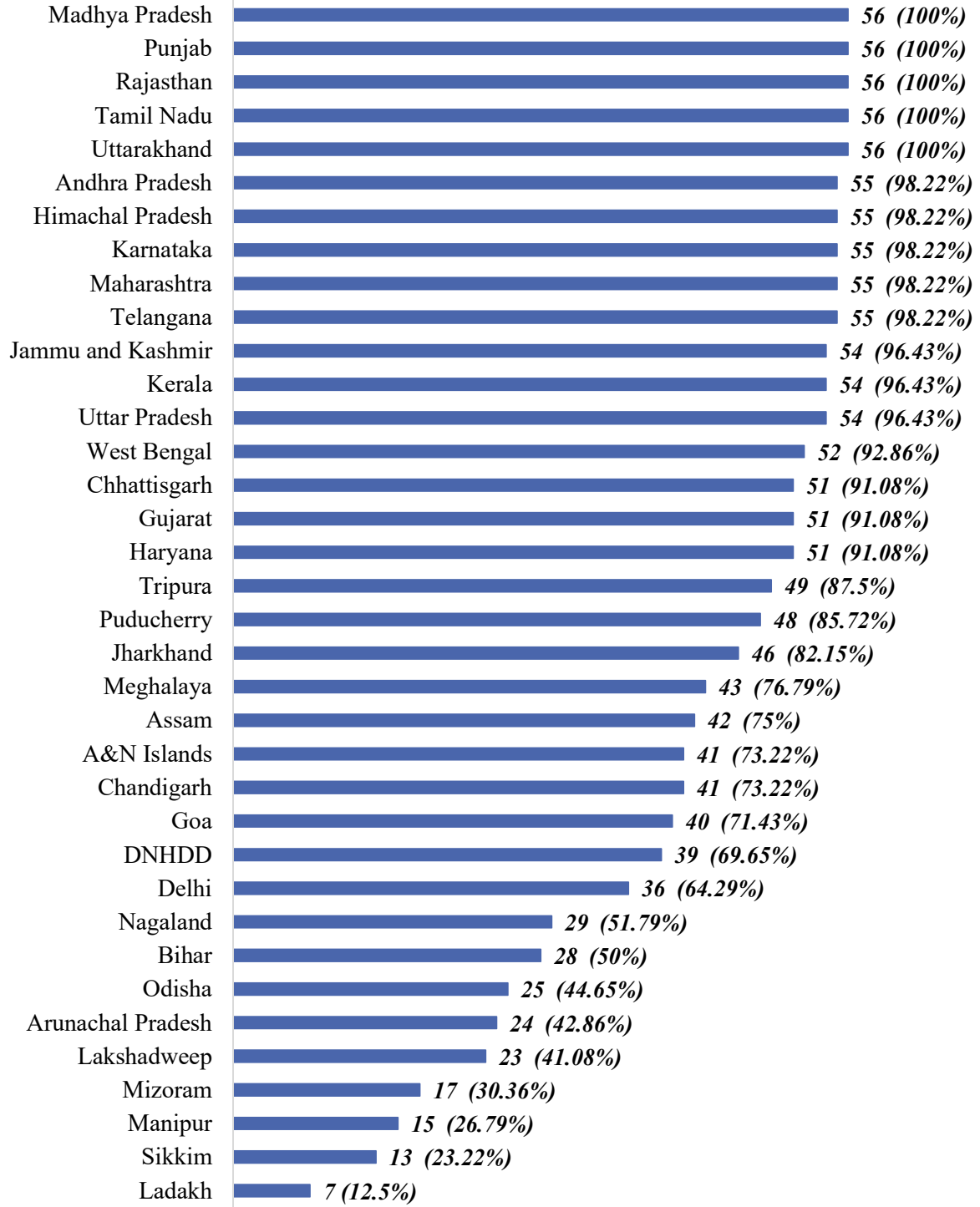
अनिवार्य ई-सेवाएँ

1,528

नोट: उपरोक्त आंकड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 05/03/2024 तक अपलोड किए गए हैं।



56 अनिवार्य ई-सेवाओं की स्थिति
नेस्टा - वे फॉरवर्ड डैशबोर्ड पर इनपुट के अनुसार



नोट: उपरोक्त आंकड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 05/03/2024 तक अपलोड किए गए हैं।

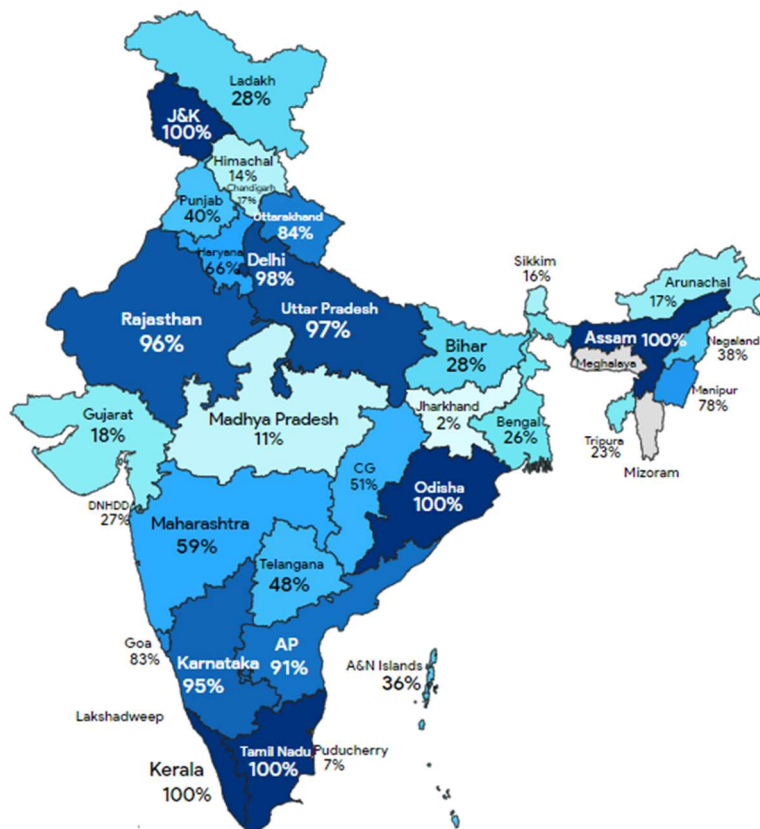
4. एकीकृत सेवा प्रदायगी पोर्टल

4.1. परिपूर्णता स्थिति

डीएआरपीजी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए अपनी ई-सेवा प्रदायगी क्षमताओं को बढ़ाने और नागरिकों और सरकार को करीब लाने के लिए फेसलेस और सुओ-मोटो पात्रता आधारित सेवाओं की प्रदायगी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक एकीकृत सेवा प्रदायगी पोर्टल के माध्यम से ई-सेवाओं के प्रावधान को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करता है।

एक एकीकृत सेवा प्रदायगी पोर्टल बेहतर शासन और सेवा उपलब्धता प्रदान करने के लिए विभागों में सेवाओं को निर्बाध रूप से एकीकृत करता है। इनसे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि सभी नागरिक अधिकार क्लाउड पर उपलब्ध हैं, कारोबार में सुगमता में वृद्धि होती है और विकास गतिविधियों के लिए कई प्रौद्योगिकियों को एकीकृत किया जाता है।

ई-सेवाओं का हिस्सा (%)
आइडेंटिफाइड सिंगल यूनिफाइड सर्विस डिलीवरी पोर्टल पर उपलब्ध



राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अभिचिन्हित सिंगल एकीकृत पोर्टल	यूआरएल	सिंगल यूनिफाइड पोर्टल पर ई- सेवा % (गणना)
तमिलनाडु	ई-सेवई	tnesevai.tn.gov.in	100% (1128)
जम्मू एवं कश्मीर	ई-उन्नत	eunnat.jk.gov.in	100% (1119)
केरल	ई-सेवानम	services.kerala.gov.in	100% (911)
असम	सेवा सेतु	sewasetu.assam.gov.in	100% (469)
ओडिशा	ओडिशा वन	odishone.gov.in	100% (404)
दिल्ली	ई-डिस्ट्रिक्ट	edistrict.delhi.gov.in	98% (426)
उत्तर प्रदेश	निवेश मित्र एवं ई-डिस्ट्रिक्ट	niveshmitra.up.nic.in & edistrict.up.gov.in	97% (774)
राजस्थान	ई-मित्रा	emitra.rajasthan.gov.in	96% (529)
कर्नाटक	सेवासिंधु	sevasindhu.karnataka.gov.in	95% (721)
आंध्र प्रदेश	एपी सेवा	vswsonline.ap.gov.in	91% (524)
उत्तराखंड	अपुनि सरकार	eservices.uk.gov.in	84% (724)
गोवा	गोवा ऑनलाइन	goaonline.gov.in	83% (199)
मणिपुर	ई-डिस्ट्रिक्ट	eservicesmanipur.gov.in	78% (31)
हरियाणा	सरल हरियाणा	saralharyana.gov.in	66% (503)
महाराष्ट्र	आपले सरकार	aaplesarkar.mahaonline.gov.in	59% (314)
छत्तीसगढ़	ई-डिस्ट्रिक्ट	edistrict.cgstate.gov.in	51% (147)
तेलंगाना	मी सेवा	ts.meeseva.telangana.gov.in	48% (365)
पंजाब	कनेक्ट पंजाब	connect.punjab.gov.in	40% (196)
नगालैंड	ई-डिस्ट्रिक्ट	edistrict.nagaland.gov.in	38% (24)
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	ई-डिस्ट्रिक्ट	edistrict.andaman.gov.in	36% (114)
लद्दाख	ई-सेवा	eseva.ladkh.gov.in	28% (13)
बिहार	आरटीपीएस बिहार	serviceonline.bihar.gov.in	28% (66)
डीएनएचडीडी	सिंगल विंडो पोर्टल	swp.dddgov.in	27% (21)
पश्चिम बंगाल	ई-डिस्ट्रिक्ट	edistrict.wb.gov.in	26% (105)
त्रिपुरा	ई-डिस्ट्रिक्ट	edistrict.tripura.gov.in	23% (60)
गुजरात	डिजिटल गुजरात	Digitalgujarat.gov.in	18% (81)
चंडीगढ़	सेवा प्लस	serviceonline.gov.in	17% (39)
अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल ई-सेवा	eservice.arunachal.gov.in	17% (53)
सिक्किम	सिक्किम एसएसओ	sso.sikkim.gov.in	16% (8)
हिमाचल प्रदेश	ई-डिस्ट्रिक्ट	edistrict.hp.gov.in	14% (69)
मध्य प्रदेश	एमपी ऑनलाइन	mponline.gov.in	11% (109)
पुदुचेरी	ई-डिस्ट्रिक्ट	edistrict.py.gov.in	7% (44)
झारखंड	झारसेवा	Jharsewa.jharkhand.gov.in	2% (8)
मेघालय	मेघालय ऑनलाइन	meghalayaonline.gov.in	-

नोट: एकल एकीकृत पोर्टलों का उपरोक्त विवरण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नेस्टा - वे फॉरवर्ड डैशबोर्ड पर 05/03/2024 तक सूचित और अपलोड किए गए हैं। लक्षद्वीप और मिजोरम में एक भी एकीकृत सेवा पोर्टल नहीं है। जिन राज्यों ने नेस्टा - वे फॉरवर्ड डैशबोर्ड पर अपने एकल एकीकृत सेवा पोर्टल के माध्यम से अपनी सेवाओं का URL अपलोड नहीं किया है, उन्हें (-) चिह्नित किया गया है

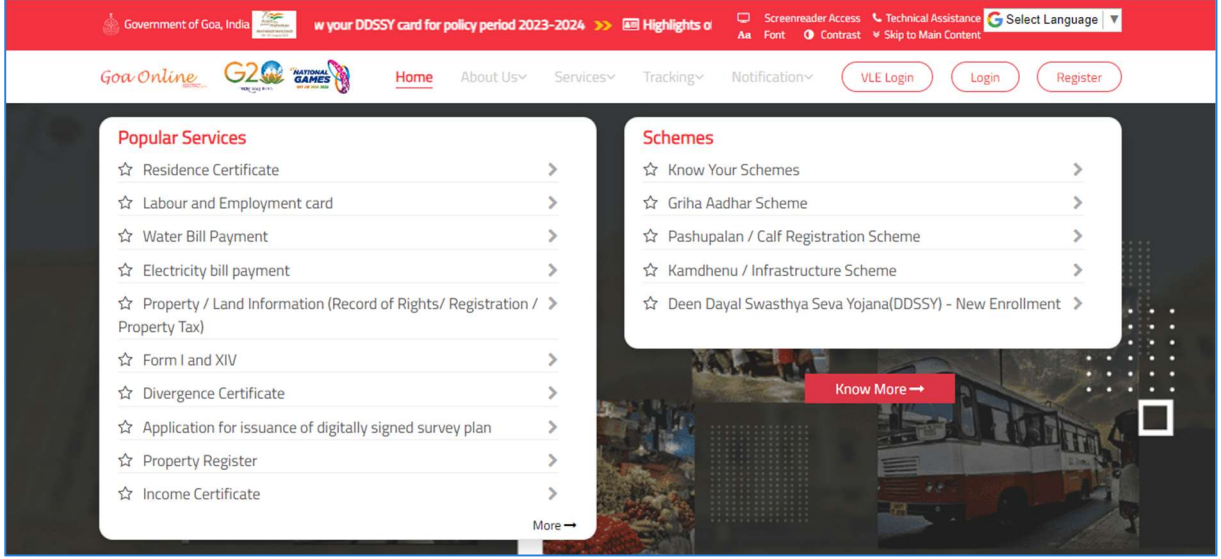
4.2. सर्वोत्तम परिपाटियाँ- एकीकृत सेवा प्रदायगी पोर्टल

नागरिक सेवा प्रदायगी के लिए पोर्टलों के एकीकरण की दिशा में एक प्रवृत्ति देखी गई है क्योंकि कई नैशनैलिटीज और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सेवा प्रदायगी के लिए एकीकृत पोर्टल विकसित किए गए हैं। ये प्रयोक्ताओं को विभिन्न सेवाओं के लिए एक एकीकृत पहुंच बिंदु प्रदान करते हैं और नेस्टा द्वारा प्रोत्साहित की जाने वाली सर्वोत्तम परिपाटियों में निहित हैं। विभिन्न विभागों या न्यायक्षेत्रों में सेवाओं को निर्बाध रूप से एकीकृत करके, वे बेहतर शासन और सेवा उपलब्धता प्रदान करते हैं। इनसे यह सुनिश्चित करने में भी मदद मिलती है कि सभी नागरिक अधिकार पोर्टेबल हैं और क्लाउड पर उपलब्ध हैं। इनमें से कई पोर्टलों ने राष्ट्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर कारोबार करने में आसानी में वृद्धि के लिए सेवाओं को डिजिटल रूप से बदल दिया है और निर्णय समर्थन और विकास गतिविधियों के लिए स्थापित और उभरती हुई विभिन्न प्रौद्योगिकियों को एकीकृत किया है।

सेवाओं की एकीकृत और निर्बाध प्रदायगी नेस्टा ढांचे का मुख्य सिद्धांत है और ऐसे पोर्टलों को सुदृढ़ करने से नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण बढ़ेगा। एकीकृत सेवा प्रदायगी में सर्वोत्तम परिपाटियों के लिए इस खंड में जिन कुछ पोर्टलों और डिजिटल पहलों पर प्रकाश डाला गया है उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पहल का नाम
1	गोवा	गोवा ऑनलाइन
2	महाराष्ट्र	आपले सरकार
3	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ ई-डिस्ट्रिक्ट
4	तेलंगाना	मी सेवा
5	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	अंडमान ई-डिस्ट्रिक्ट
6	बिहार	सेवा ऑनलाइन

4.2.1. गोवा ऑनलाइन



<https://goaonline.gov.in/>

गोवा सरकार ने सभी सरकारी सेवाओं को सामान्य सेवा प्रदायगी आउटलेट के माध्यम से अपने इलाके में आम नागरिक के लिए सुलभ बनाने के लिए गोवा ऑनलाइन विकसित किया है।

Key Features

- ✓ नागरिक और प्रशासक के लिए लॉगिन और डैशबोर्ड
- ✓ सेवाओं को चुनने और लागू सेवाओं को जानने में मदद करने की सुविधा
- ✓ विभागवार वर्गीकृत ई-सेवाएँ और उनका विवरण उपलब्ध है
- ✓ पावती संख्या का उपयोग करके आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने का प्रावधान
- ✓ डिजीलॉकर के साथ एकीकृत
- ✓ ई-सेवा आवेदन स्थिति के लिए विस्तृत डैशबोर्ड व्यू उपलब्ध है
- ✓ संपर्क और हेल्पडेस्क विवरण उपलब्ध है
- ✓ फीडबैक देने का प्रावधान
- ✓ स्क्रीन फ्रॉन्ट साइज और कंट्रास्ट बदलने की कार्यक्षमता
- ✓ विस्तृत एक्सेसिबिलिटी मेनू उपलब्ध है, जो इसे प्रयोक्तानुकूल बनाता है

225+
ई-सर्विसेज

23 लाख+
ई-लेनदेन की संख्या

12 लाख+
प्रमाणपत्र मुद्दे

7 लाख+
पंजीकृत प्रयोक्ता

4.2.2. आपले सरकार

The screenshot displays the Aaple Sarkar website interface. At the top, there is a navigation bar with links for HOME, ABOUT RTS COMMISSION, DEPARTMENT NOTIFIED SERVICES, EASE OF DOING BUSINESS, SERVICE INFORMATION, CONTACT US, SEWA KENDRA, and DASHBOARD. Below this, a 'Know Your Benefits' dropdown menu is visible. The main content area is titled 'SERVICES AVAILABLE ONLINE' and includes a search bar and a list of services such as Age Nationality Domicile, Income Certificate, Senior Citizen Certificate, and others. On the right side, there are sections for 'FAQs & Answers on Maharashtra Right to Public Services Act', 'Annual Report 2021-2022', and 'CITIZEN LOGIN' with options for 'New User? Register Here...' and 'VLE Login'. There is also a 'TRACK YOUR APPLICATION' section and a 'CALL CENTER' link.

<https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in/>

महाराष्ट्र सरकार ने नागरिकों को आरटीएस अधिनियम के तहत उपलब्ध सेवाओं के बारे में जानकारी तक पहुंच प्रदान करने के लिए *आरटीएस महाराष्ट्र* मोबाइल ऐप या *आपले सरकार वेब पोर्टल डिज़ाइन किया है*। पर्याप्त औचित्य के बिना सेवा प्रदायगी में देरी के मामले में, नागरिक विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष पहली और दूसरी अपील दायर कर सकते हैं और तीसरी और अंतिम अपील आयोग के समक्ष दायर की जा सकती है।

Key Features

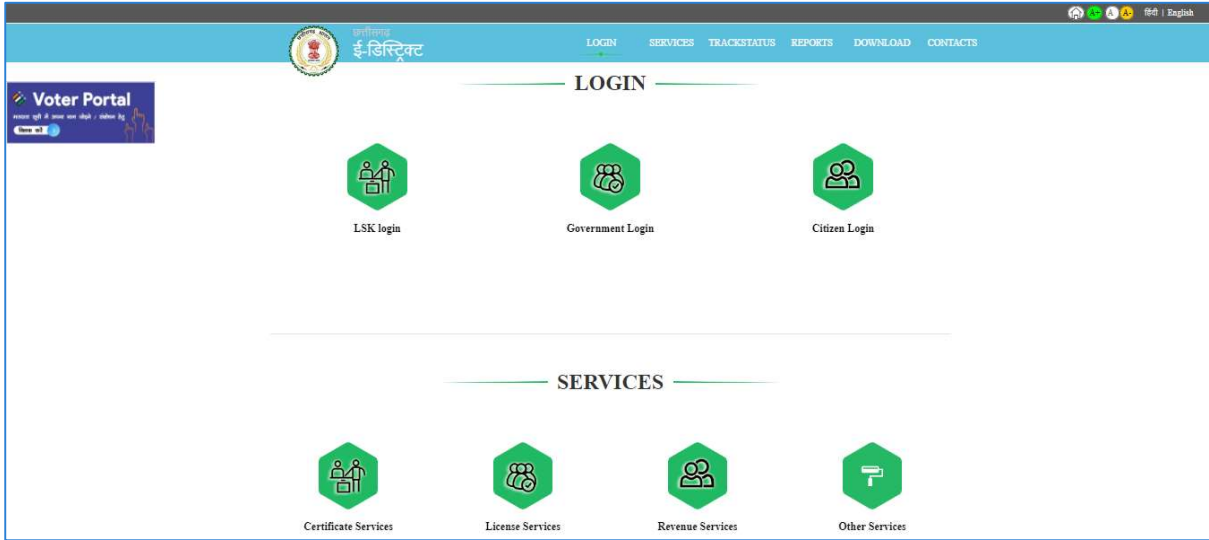
- ✓ नागरिक और वीएलई के लिए लॉगिन और डैशबोर्ड
- ✓ डिजीलॉकर, आधार और पे गव इंडिया के साथ एकीकृत
- ✓ विभागवार वर्गीकृत ई-सेवाएँ और उनका विवरण उपलब्ध है
- ✓ सेवा केंद्र का पता लगाने की सुविधा
- ✓ एप्लिकेशन आईडी का उपयोग करके एप्लिकेशन की स्थिति को ट्रैक करने का प्रावधान
- ✓ ईओडीबी अधिनियमों, नीतियों और सुधारों पर विस्तृत जानकारी
- ✓ सांख्यिकी का विस्तृत डैशबोर्ड व्यू
- ✓ डब्लू 3 सी के अनुरूप
- ✓ एंड्रॉइड (गूगल प्ले स्टोर) और आईओएस (ऐप स्टोर) पर मोबाइल ऐप के लिंक उपलब्ध है
- ✓ अंग्रेजी, मराठी में भी उपलब्ध है
- ✓ संपर्क, हेल्पलाइन और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न उपलब्ध है

426
ई-सेवाएँ

1387,04,656
प्राप्त हुए आवेदन

13,18,33,860
निस्तारित आवेदन

4.2.3. छत्तीसगढ़ ई-डिस्ट्रिक्ट



<https://edistrict.cgstate.gov.in/>

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में ई-गवर्नेंस पहल शुरू की है। छत्तीसगढ़ ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के रूप में जानी जाने वाली इस पहल का उद्देश्य पारदर्शिता, दक्षता बढ़ाना और अपने नागरिकों को उच्च गुणवत्ता युक्त और समय पर सेवाएं प्रदान करना है। परियोजना आधिकारिक तौर पर 27 फरवरी, 2015 को शुरू की गई थी। वेबसाइट एप्लिकेशन, रिपोर्ट की स्थिति, डाउनलोड और संपर्क सूचना सहित सेवाएं प्रदान करती है, और ये सेवाएं 24/7 उपलब्ध हैं और इसका एक मोबाइल ऐप भी है।

Key Features

- ✓ छत्तीसगढ़ सेवा का अधिकार (आरटीएस) अधिनियम के साथ एकीकृत
- ✓ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार सेवा स्तर की निगरानी
- ✓ आवेदन स्थिति की ट्रैकिंग
- ✓ नागरिक लॉगिन और सेवा पहुंच
- ✓ सिस्टम-जनरेटेड एसएमएस अलर्ट
- ✓ राज्यव्यापी सेवा स्थिति डैशबोर्ड
- ✓ डैशबोर्ड और रिपोर्ट प्रतिदिन अद्यतन की जाती हैं
- ✓ बहुभाषी समर्थित
- ✓ मोबाइल ऐप की उपलब्धता
- ✓ नागरिक सेवा नियमों तक आसानी से पहुंच
- ✓ वर्तमान में, छत्तीसगढ़ ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से 126 सेवाएं उपलब्ध हैं

4.2.4. मीसेवा

Home Services Gallery Downloads Other Links Grievance MeeSeva Centres Contact Us

Important Alerts !

Citizen Services Search for Service

RTA GHMC TSPDCL Police

Registration Revenue Twallet HMVSSB

Endowment Other Payments Agriculture CDMA

Login

Staff code / Franchise code / Login id

Password

Show Password

Login

New User Forget Password

Welcome To MeeSeva Portal

"MeeSeva" in Telugu means, 'At your service', i.e. service to citizens. It is a good governance initiative that incorporates the vision of National eGov Plan "Public Services Closer to Home" and facilitates single entry portal for entire range of G2C& G2B services.

Know Your Application Status

Know Your Application Status

MeeSeva Certificate (Application No)

MeeSeva Certificate (Application No)

<https://ts.meeseva.telangana.gov.in/>

मीसेवा, जिसका तेलुगु में अर्थ है "आपकी सेवा में", सुशासन के प्रति तेलंगाना सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। राष्ट्रीय ई-गव योजना के "घर के करीब सार्वजनिक सेवाएं" के दृष्टिकोण के अनुरूप, मीसेवा गवर्नमेंट-टू-सिटीजन (जी2सी) और गवर्नमेंट-टू-बिजनेस (जी2बी) सेवाओं की एक व्यापक श्रृंखला के लिए एकल, एकीकृत पोर्टल प्रदान करता है। नागरिक विभिन्न चैनलों, ऑनलाइन पोर्टल, मीसेवा सेवा केंद्र, या टी ऐप फोलियो मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से मीसेवा सेवाओं तक पहुंच सकते हैं।

Key Features

- ✓ प्रयोक्ताओं को सूचित करने के लिए प्रमुख सतर्कता संदेशों पर स्पष्ट रूप से प्रकाश डाला गया
- ✓ संगत सेवाओं को देखने के लिए विभाग-विशिष्ट खोज
- ✓ सरकारी आदेशों, नीतिगत दस्तावेजों और अन्य सहायक सामग्री आसानी से उपलब्ध हैं
- ✓ मीसेवा साइबर सुरक्षा नीति और तेलंगाना ओपन डेटा नीति तक ओपन पहुंच
- ✓ मीसेवा सेंटर लोकेटर, एक इंटरैक्टिव मैप है
- ✓ मुख्यपृष्ठ नवीनतम अपडेट और घोषणाओं पर प्रकाश डालता है
- ✓ मीसेवा रिक्वेस्ट ट्रैकिंग सिस्टम (एमआरटीएस) आवेदनों की स्थिति को ट्रैक करने की अनुमति देता है
- ✓ आवेदन संख्या प्रदान करके क्लोज्ड ऐप्लिकेशन को फिर से खोलने की प्रक्रिया
- ✓ पोर्टल के माध्यम से विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए नागरिकों को एक अकाउंट बनाना होगा



4.2.5. अंडमान ई-डिस्ट्रिक्ट

<https://edistrict.andaman.gov.in/>

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) के तहत स्थापित एक मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) है जिसे सोवटेक द्वारा कार्यान्वित किया गया है। यह एमएमपी विशेष रूप से जिला और उप-जिला स्तरों पर प्रदान की जाने वाली हाई वॉल्यूम नागरिक-केंद्रिक सेवाओं को लक्षित करता है जो अन्य मिशन मोड परियोजनाओं के अंतर्गत शामिल नहीं हैं। परियोजना के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के विभिन्न विभागों में 78 अभिचिन्हित नागरिक सेवाओं को प्रचार करने और उन्हें लागू करने की योजना बनाई गई है।

Key Features

- ✓ लॉगिन और वैयक्तिकृत डैशबोर्ड नागरिकों को सेवाओं तक पहुंचने के लिए सुविधाजनक और व्यवस्थित अनुभव प्रदान करते हैं
- ✓ विस्तृत विवरण के साथ ई-सेवाओं का विभाग-वार वर्गीकरण
- ✓ नागरिक अपने विशिष्ट आवेदन नंबर का उपयोग करके आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं
- ✓ फीडबैक तंत्र प्रयोक्ताओं को सुधार के लिए मूल्यवान जानकारी प्रदान करता है
- ✓ प्रश्न पूछने का प्रावधान नागरिकों को विशिष्ट सेवाओं पर स्पष्टीकरण मांगने में सक्षम बनाता है
- ✓ विशिष्ट संपर्क जानकारी, एक हेल्पलाइन नंबर और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
- ✓ पोर्टल W3C मानकों का पालन करता है, जो विभिन्न ब्राउज़रों में पहुंच और इष्टतम प्रयोक्ता अनुभव सुनिश्चित करता है
- ✓ समर्थित ब्राउज़रों में फ़ायरफ़ॉक्स (24.0 संस्करण और इससे ऊपर), गूगल क्रोम (35.0 संस्करण और इससे ऊपर), और सफारी (6.0 संस्करण और इससे ऊपर) शामिल हैं।

4.2.6. सेवा ऑनलाइन

<https://serviceonline.bihar.gov.in/>

ई-डिस्ट्रिक्ट बिहार, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) के तहत कार्यान्वित एक मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) है। यह पहल नागरिकों को वन-स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करने वाली सरकारी सेवाएं सुविधाजनक रूप से उपलब्ध कराने पर केंद्रित है, जो कहीं से भी अभिगम्य है।

यह परियोजना बिहार में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी) द्वारा क्रियान्वित की गई है, जो भारत के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा विकसित शिकायत निवारण सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है। यह फ्रेमवर्क बिहार में ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के कार्यान्वयन को सुकर और सक्षम बनाता है।

Key Features

- ✓ विभिन्न सरकारी प्लेटफार्मों के साथ एकीकृत: मेरीपहचान (नेशनल सिंगल साइन-ऑन), सर्विस प्लस, एनआईसी ई-मेल, सी-डैक एसएमएस सेवा, आधार जनसांख्यिकी, यूआईडीएआई ओटीपी प्रमाणीकरण, ओजीआरएस पेमेंट गेटवे, डिजीलॉकर, डीएससीसाइन, ई-साइन, आरएस, और ई-ताल
- ✓ नागरिकों के लिए लॉगिन और वैयक्तिकृत डैशबोर्ड
- ✓ ई-सेवाओं का विभाग एवं क्षेत्रवार वर्गीकरण
- ✓ बहुभाषी सुलभता
- ✓ नागरिक एक विशिष्ट संदर्भ संख्या का उपयोग करके आवेदन की स्थिति की निगरानी कर सकते हैं

65

ई-सेवाएं

121,315,110

प्राप्त आवेदन

106,279,778

वितरित किए गए आवेदन

5. पूर्वोत्तर राज्यों में ई-सेवा प्रदायगी को सुदृढ़ करना

नेस्डा के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक भारत की ई-गवर्नेंस प्रगति का विश्लेषण करना, ई-सेवाओं के विस्तार को बढ़ावा देना और एकीकृत सेवा प्रदायगी पोर्टलों के उपयोग को बढ़ावा देना है। नेस्डा के अनुरूप, डीएआरपीजी का लक्ष्य पूर्वोत्तर राज्यों में ई-सेवा प्रदायगी परिदृश्य में सुधार करना है, जिससे उनके समग्र नेस्डा स्कोर में वृद्धि की सुविधा मिल सके।

इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, पूर्वोत्तर राज्य आसान पहुँच और कुशल प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रमुख एकीकृत सेवा प्रदायगी पोर्टल के तहत सभी ई-सेवाओं को समेकित कर सकते हैं। यह ई-सेवाओं को एकीकृत करने में आने वाली चुनौतियों की पहचान करके और उनका समाधान करके और यदि आवश्यक हो तो पोर्टल अवसंरचना के लिए सर्विस प्लस/माई स्कीम (इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) के साथ एकीकृत करने के लिए बैठकें आयोजित करके सहयोगात्मक रूप से समाधान ढूँढकर किया जा सकता है।

इस उद्देश्य से, मणिपुर सरकार के अनुरोध पर, डीएआरपीजी ने मणिपुर के एकीकृत सेवा प्रदायगी पोर्टल को सुदृढ़ करने के लिए मणिपुर सरकार और जम्मू और कश्मीर सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच 19-20 फरवरी, 2024 को 2-दिवसीय बैठकों का आयोजन किया। दो दिवसीय विचार-विमर्श में एमईआईटीवाई और डीएआरपीजी के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। व्यापक चर्चा के बाद, मणिपुर सरकार में ई-सेवाओं में सुधार और वृद्धि का रोडमैप तैयार किया गया। मणिपुर सरकार का लक्ष्य सार्वजनिक सेवा प्रदायगी दक्षता में सुधार करने के लिए अपने ई-गवर्नेंस अवसंरचना को बढ़ाना है, ताकि पहले चरण में राजस्व, गृह, उद्योग और वाणिज्य, समाज कल्याण, पीडब्ल्यूडी, और पी.एच.ई.डी. विभागों को शामिल करते हुए अपने ऑनलाइन सेवा पोर्टफोलियो को 35 से 150 तक विस्तारित किया जा सके। ऑनलाइन सेवाओं के दायरे को व्यापक बनाकर, मणिपुर का लक्ष्य पहुंच और दक्षता को बढ़ाना है, जिससे सरकारी एजेंसियों के साथ बातचीत करने वाले नागरिकों के समग्र अनुभव में सुधार होगा। मणिपुर और जम्मू-कश्मीर के बीच सहयोगात्मक प्रयासों के परिणामस्वरूप एक व्यापक रोडमैप का विकास हुआ है।



19 फरवरी 2024 को मणिपुर सरकार और जम्मू-कश्मीर सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक

6. सामान्य ई-सेवाएँ

देश भर में ई-सेवा प्रदायगी अनुभव को बढ़ाने के लिए नेस्टा वे फॉरवर्ड के उद्देश्य के अनुरूप, डीएआरपीजी ने विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सेवा का अधिकार (आरटीएस) अधिनियम के मुख्य आयुक्तों और अपीलीय अधिकारियों के साथ एक सहयोगात्मक पहल शुरू की है। विभाग ने क्रमशः 16.06.2023 और 09.10.2023 को दो वर्चुअल बैठकें आयोजित की।

आरटीएस मुख्य आयुक्तों के साथ विचार-विमर्श के अनुसार, अनिवार्य ई-सेवाओं के दायरे को अभिचिन्हित करने और अधिकतम संख्या तक बढ़ाने और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उच्च मात्रा वाली ई-सेवाओं के प्रावधान का विस्तार करने में मदद करने के लिए पहल की गई थी। डीएआरपीजी ने 154 सामान्य ई-सेवाओं के एक सेट की पहचान की है, और इसे सितंबर 2023 में नेस्टा वे फॉरवर्ड डैशबोर्ड पर सामान्य सेवा टैब पर पेश किया है।

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध है कि वे अपनी सामान्य सेवाओं को नेस्टा वे फॉरवर्ड डैशबोर्ड पर मैप करें।

S.No.	Common Service	Andaman and Nicobar Islands	Andhra Pradesh	Arunachal Pradesh	Assam	Bihar	Chandigarh	Chhattisgarh	Dadra and Nagar Haveli & Daman and Diu
1	Addition/Continuation/Termination of Hypothecation	No	No	No	No	No	No	No	No
2	Addition/ Deletion of weapon (if the license issuing district is the same where service has been sought) From the expiry of the mandatory notice period of 45 days as provided under the Arms Act	No	No	No	No	No	No	No	No
3	Addition of new class to Driving License	No	No	No	No	No	No	No	No

नेस्टा वे फॉरवर्ड डैशबोर्ड पर सामान्य सेवा टैब

7. सेवा प्रदायगी की गुणवत्ता में सुधार

दुनिया भर में समकालीन डिजिटल सरकारी रुझानों और नागरिकों की आवश्यकता के अनुरूप, नेस्डा फ्रेमवर्क में तीन नए अतिरिक्त मूल्यांकन पैरामीटर अर्थात् *ओपन गवर्नमेंट डेटा*, *ई-भागीदारी* और *उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना* शामिल किए गए हैं।

इन मापदंडों को सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता, नागरिक जुड़ाव और नवाचार को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण घटकों के रूप में पहचाना गया है। इसलिए, यह जरूरी है कि सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र नीचे उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार इन मापदंडों को अपने संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पोर्टल में एकीकृत करें।

- 1. ओपन गवर्नमेंट डेटा (ओजीडी):** नियामक फ्रेमवर्क के अनुरूप सरकार के स्वामित्व वाले साझा करने योग्य डेटा और इसके उपयोग की जानकारी तक सक्रिय पहुंच
 - एक समर्पित ओजीडी पोर्टल या ओजीडी प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित डेटासेट (data.gov.in)
 - राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पोर्टल पर ओजीडी प्लेटफॉर्म लिंक का एकीकरण
 - एक मुख्य डेटा अधिकारी की नियुक्ति जो डेटा-संबंधित पहलों की देखरेख करता है
 - नेस्डा 2023 के कम से कम चार क्षेत्रों के सुलभ डेटासेट पर प्रकाश डाला गया और सार्वजनिक किया गया
 - जीआईएस मैप और भू-स्थानिक डेटा डाउनलोड करने का प्रावधान
 - जनता को नए डेटासेट के लिए अनुरोध करने की अनुमति दें
 - ओजीडी पोर्टल के उपयोग पर ट्यूटोरियल, मार्गदर्शन सामग्री और वीडियो की उपस्थिति
 - ओजीडी पोर्टल और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पोर्टल पर डेवलपर समुदाय को शामिल करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का प्रलेखन
- 2. ई-भागीदारी:** *आईसीटी* के माध्यम से सरकारों और नागरिकों के बीच बातचीत नागरिकों को नीतियों और सेवाओं का सह-डिज़ाइन करने के लिए सशक्त बनाती है
 - राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पोर्टल पर ई-भागीदारी नीति प्रकाशित की गई
 - मार्गव पोर्टल में एक समर्पित ई-भागीदारी पोर्टल या उप-साइट की स्थापना
 - राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पोर्टल के मुख्यपृष्ठ पर ई-भागीदारी पोर्टल लिंक का एकीकरण
 - ई-भागीदारी पोर्टल के मुख्यपृष्ठ पर सभी आगामी ई-भागीदारी और ई-परामर्श गतिविधियों के कैलेंडर और परिणामों का समावेश
 - पोर्टल के उपयोग पर ट्यूटोरियल, मार्गदर्शन सामग्री और वीडियो की मौजूदगी
 - ई-भागीदारी पोर्टल और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पोर्टल पर ई-भागीदारी और ई-परामर्श पहल के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का प्रलेखन

3. उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना: सरकार के डिजिटल विकास और उन्नत सेवा प्रदायगी के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों को रणनीतिक रूप से अपनाना

- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पोर्टल पर एआई और ब्लॉकचेन, आईओटी, बिग डेटा, रोबोटिक्स, संवर्धित रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी या 5जी जैसी अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के रणनीतिक दस्तावेज़/पहुँच की मौजूदगी।
- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पोर्टल पर एआई-आधारित सेवा चैटबॉट (अंग्रेजी और स्थानीय भाषा) का प्रावधान
- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पोर्टल पर सेवा प्रदायगी में अपनाई गई किसी भी अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों का प्रलेखन

इन तीन अतिरिक्त मापदंडों की निगरानी अब नेस्डा वे फॉरवर्ड में की जाएगी, जो नेस्डा 2025 के लिए एक प्रारंभिक मंच के रूप में कार्य करती है। इन मापदंडों के कार्यान्वयन की स्थिति को अद्यतन करने का प्रावधान शीघ्र ही नेस्डा वे फॉरवर्ड डैशबोर्ड पर सक्षम किया जाएगा।

1. मीडिया आउटरीच



DARPG releases the Annual NeSDA Way Forward Report for 2023 – Significant progress achieved in e-Services Delivery by States/ UTs

3 Regional Conferences organized on e-Governance in Bhopal, Mumbai and Guwahati

16,487 Total e-services are provided across States/UTs

9 NeSDA Way Forward Monthly Reports for States/UTs published

Jammu and Kashmir provides the maximum (1117) number of e-Services, across States/UTs

76% Mandatory e-services are available i.e., 1,528 out of 2,016 (56*36 States/UTs), an increase from 69% under NeSDA 2021

Meetings with RTS Commissioners / Appellate Officers for improving e-Services delivery

A brainstorming session was conducted on 04.01.2024 on the theme- Emerging and Future e-Governance Initiatives, e-Commerce Initiatives, and Emerging Technologies

Posted On: 08 FEB 2024 1:34PM by PIB Delhi



DARPG
@DARPG_GoI

...

DARPG coordinates collaboration between Governments of Manipur and Jammu & Kashmir for Enhanced e-Service Delivery through saturation of e-services and promote the utilization of unified service delivery portals in Manipur.

#Collaboration #NeSDA #NorthEast



PMO India and 8 others



DARPG coordinates collaboration between Governments of Manipur and Jammu & Kashmir for Enhanced e-Service Delivery through saturation of e-services and promote the utilization of unified service delivery portals in Manipur

2-days of meetings between Senior Officials of DARPG, Governments of Manipur and Jammu & Kashmir held on 19- 20 February 2024

The objective is to significantly expand Government of Manipur's online service portfolio from 35 to 150, in the first phase

Senior Officers from Service Plus and UMANG teams of Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) provided valuable insights on service integration and utilization of existing cost-effective digital infrastructure

Posted On: 20 FEB 2024 5:36PM by PIB Delhi

Digital India • 2 Min Read

NeSDA Way Forward: DARPG coordinates digital collaboration between Manipur, J&K

Following extensive discussions, the roadmap for improvements and increase in e-services in Government of Manipur was formulated.



Online Bureau • Agencies

Updated On Feb 23, 2024 at 08:19 AM IST

Read by:

2274 Industry Professionals



DARPG coordinated two days of meetings on February 19-20 between senior officials of Manipur and Jammu & Kashmir in strengthening the unified service delivery portal of Manipur.

The Department of Administrative Reforms and Public Grievances (DARPG) has undertaken the National e-Governance Service Delivery Assessment (NeSDA) way forward with the aim to saturate e-services and promote the utilization of unified service delivery portals.

 **The Indian EXPRESS**
JOURNALISM OF COURAGE

News / India / Jammu & Kashmir tops in delivering e-services, Manipur at the bottom: Report

Jammu & Kashmir tops in delivering e-services, Manipur at the bottom: Report

The 'Annual NeSDA Way Forward Report 2023', released by the Department of Administrative Reforms and Public Grievances, shows that Jammu & Kashmir dominated with 1,117 e-services, followed by Tamil Nadu, Madhya Pradesh and Kerala.

2. अनुबंध

9.1. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ई-सेवाओं की स्थिति की मासिक प्रगति

#	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अप्रैल' 23	मई' 23	जून' 23	जुलाई' 23	अगस्त' 23	सितम्बर' 23	अक्टूबर' 23	नवंबर' 23	दिसंबर' 23	जनवरी और फरवरी'24
1	तमिलनाडु	446	445	445	445	446	446	446	1078	1101	1128
2	जम्मू एवं कश्मीर	474	469	469	470	1028	1034	1075	1097	1117	1119
3	मध्य प्रदेश	637	731	948	1000	1010	1010	1010	1010	1010	1010
4	केरल	885	886	911	911	911	911	911	911	911	911
5	उत्तराखंड	596	595	595	725	782	826	831	865	865	865
6	उत्तर प्रदेश	709	706	713	714	714	714	798	798	798	798
7	तेलंगाना	493	491	582	757	768	768	768	768	768	768
8	हरियाणा	762	757	757	757	757	755	757	757	757	757
9	कर्नाटक	779	747	752	752	752	752	752	755	755	755
10	पुदुच्चेरी	239	239	239	239	246	247	247	325	605	605
11	आंध्र प्रदेश	606	574	579	579	579	579	579	579	579	579
12	राजस्थान	248	248	248	525	536	547	549	549	549	549
13	महाराष्ट्र	150	148	337	441	521	533	533	533	533	533
14	हिमाचल प्रदेश	500	494	500	500	500	500	500	500	500	501
15	पंजाब	486	483	484	484	484	484	484	484	484	484
16	असम	263	259	259	259	259	452	469	469	469	469
17	गुजरात	191	228	444	443	443	443	443	443	443	443
18	दिल्ली	412	416	416	436	436	436	436	436	436	436
19	ओडिशा	211	373	383	383	404	404	404	404	404	404
20	पश्चिम बंगाल	290	323	401	401	401	401	401	401	401	401
21	मेघालय	252	217	223	223	249	306	340	363	363	363
22	झारखंड	316	294	310	311	333	333	333	333	333	333
23	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	164	171	171	199	200	206	239	239	321	321
24	अरुणाचल प्रदेश	34	101	298	298	309	309	309	309	309	309
25	छत्तीसगढ़	272	270	284	284	284	284	287	287	287	287
26	त्रिपुरा	233	230	251	262	267	270	269	269	263	263
27	गोवा	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
28	बिहार	222	234	238	238	237	237	237	238	238	238
29	चंडीगढ़	231	221	221	224	224	224	224	224	224	224
30	मिजोरम	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
31	डीएनएचडीडी	39	78	78	78	78	78	78	78	78	78
32	नगालैंड	34	34	64	64	64	64	64	64	64	64
33	सिक्किम	25	25	36	36	43	51	51	51	51	51
34	लद्दाख	32	32	32	46	46	46	46	46	46	46
35	लक्षद्वीप	-	-	-	-	42	42	42	42	42	42
36	मणिपुर	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
	कुल	11,614	11,902	13,051	13,867	14,736	15,075	15,295	16,088	16,487	16,517

9.2. चिह्नित सामान्य ई-सेवाओं की सूची

#	सामान्य ई-सेवा
1	हाइपोथिकेशन का परिवर्धन/निरंतरता/समाप्ति
2	हथियार का ऐडिशन/डिलीशन (यदि लाइसेंस जारी करने वाला जिला वही है जहां सेवा मांगी गई है) शस्त्र अधिनियम के तहत प्रावधानित 45 दिनों की अनिवार्य नोटिस अवधि की समाप्ति से
3	ड्राइविंग लाइसेंस में नई श्रेणी को जोड़ना
4	शिक्षा छात्रवृत्ति (जी2सी) के लिए आवेदन
5	प्रवासी कामगारों (जी2बी) की भर्ती के लिए ठेकेदार के लाइसेंस के लिए आवेदन
6	पोल्ट्री और पशुधन फीड के निर्माण और/या व्यापार के लाइसेंस के लिए आवेदन
7	दुकानों और प्रतिष्ठानों के पंजीकरण के लिए आवेदन (जी2बी)
8	वरिष्ठ नागरिक कार्ड के लिए आवेदन
9	खेल छात्रवृत्ति के लिए आवेदन
10	जल कनेक्शन के लिए आवेदन (व्यवसाय) (जी2बी)
11	भारतीय पंजीकरण अधिनियम (जी2सी) के तहत पंजीकरण के लिए नियुक्ति
12	भवन योजना का अनुमोदन/संशोधन
13	जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत प्राधिकरण
14	निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत प्राधिकरण (संशोधित)
15	ई-कचरा प्रबंधन नियम, 2016 के तहत प्राधिकरण
16	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत प्राधिकरण (संशोधित)
17	खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट) नियम, 2016 के तहत प्राधिकरण
18	आवास एवं परिवहन बुक करना
19	सामुदायिक केंद्र की बुकिंग
20	दूर पैकेज और पर्यटक आकर्षण बुक करना
21	भवन या विकास परमिट (जी2बी)
22	पता परिवर्तन (डीएल)
23	एफपीएस में परिवर्तन सहित पते में परिवर्तन
24	पता परिवर्तन (आरसी)
25	राशन कार्ड में एक ही क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पते में परिवर्तन
26	संपत्ति कर रजिस्टर में स्वामी/कब्जाधारी का परिवर्तन (मृत्यु मामले को छोड़कर)
27	मृत्यु के मामले में संपत्ति कर रजिस्टर में मालिक/कब्जाधारी का परिवर्तन
28	स्वामित्व में परिवर्तन (मृत्यु के मामलों को छोड़कर)
29	चरित्र प्रमाण पत्र
30	चरित्र सत्यापन
31	वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का केंद्रीय अधिनियम 14) के तहत स्थापना के लिए सहमति
32	जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का केंद्रीय अधिनियम 6) के तहत स्थापना के लिए सहमति
33	वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का केंद्रीय अधिनियम 14) के तहत संचालन की सहमति
34	जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का केंद्रीय अधिनियम 6) के तहत संचालन की सहमति
35	चोरी हुए वाहनों से संबंधित मामलों में अनट्रेसड रिपोर्ट की प्रति
36	सड़क दुर्घटना मामलों में अनट्रेसड रिपोर्ट की प्रति
37	चोरी के मामलों में अज्ञात रिपोर्ट की प्रति
38	विलंबित जन्म/मृत्यु पंजीकरण
39	प्लॉट का सीमांकन
40	विकलांगता पेंशन

41	घरेलू सहायक सत्यापन (यदि स्थानीय क्षेत्र का निवासी हो)
42	कर्मचारी पंजीकरण (जी2सी)
43	कर्मचारी सत्यापन
44	नियोक्ता पंजीकरण (जी2बी)
45	बिजली बिलों का ई-भुगतान (नागरिक) (जी2सी)
46	इवेंट/परफॉर्मेंस अनुरोध
47	हथियार की खरीद अवधि का विस्तार, (अनुमेय समय अवधि के भीतर और यदि लाइसेंस जारी करने वाला जिला वही है जहां सेवाएं मांगी गई हैं)
48	विदेशियों के आवासीय परमिट का विस्तार
49	कृषि यंत्रीकरण
50	निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता (एफएडीसी)
51	संचार एवं कनेक्टिविटी अवसंरचना स्थापित करने हेतु अनुमति प्रदान करना
52	नए शस्त्र लाइसेंस का अनुदान
53	राशन कार्ड में परिवार के सदस्य को शामिल करना/हटाना
54	खाद्य व्यवसाय संचालकों के लाइसेंस जारी करना/संशोधन/नवीनीकरण
55	आयुष्मान कार्ड जारी करना
56	जाति प्रमाण पत्र जारी करना (जी2सी)
57	अधिवास प्रमाणपत्र जारी करना (जी2सी)
58	ऋण प्रमाणपत्र जारी करना (जी2सी)
59	आय प्रमाणपत्र जारी करना (जी2सी)
60	विवाह प्रमाणपत्र जारी करना (जी2सी)
61	शहरी स्थानीय निकाय द्वारा नई संपत्ति आईडी जारी करना
62	पेट्रोल पंप, सिनेमा हॉल आदि की स्थापना के लिए एनओसी जारी करना
63	जन्म प्रमाण पत्र जारी करना/अद्यतन करना
64	मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करना/अद्यतन करना
65	विस्तृत अंक प्रमाणपत्र (डीएमसी) जारी करना/डुप्लिकेट
66	जारी करना/डुप्लिकेट प्रवासन प्रमाणपत्र
67	उत्तीर्ण डिग्री जारी करना/डुप्लिकेट
68	राशन कार्ड जारी करना/डुप्लिकेट/नवीनीकरण
69	बीज और कीटनाशक और उर्वरक के लिए लाइसेंस जारी करना/डुप्लिकेट/नवीनीकरण
70	स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना/डुप्लिकेट/नवीनीकरण
71	पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करना/डुप्लिकेट/नवीनीकरण
72	फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करना
73	भूतपूर्व सैनिकों को पहचान पत्र जारी करना
74	भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं को पहचान पत्र जारी करना
75	एनओसी/डुप्लिकेट आवंटन/पुनःआवंटन पत्र जारी करना
76	नो ड्यू सर्टिफिकेट जारी करना
77	बंधक हेतु अनुमति जारी करना
78	बस पास जारी करना/नवीनीकरण (सामान्य)
79	दिव्यांगों के लिए बस पास जारी/नवीनीकरण
80	स्कूली बच्चों को बस पास जारी करना/नवीनीकरण करना
81	बाट और माप आदि के सत्यापन के लिए प्रमाणपत्र जारी/नवीनीकरण।
82	कंडक्टर लाइसेंस जारी करना/नवीनीकरण
83	कन्वेयंस डीड जारी करना/नवीनीकरण
84	उचित मूल्य दुकान लाइसेंस जारी करना /नवीनीकरण

85	फायर एनओसी जारी करना/नवीनीकरण
86	ईंटों के निर्माण और बिक्री के लिए लाइसेंस जारी करना/नवीनीकरण (नियंत्रण आदेश में निर्धारित लाइसेंस शुल्क और सुरक्षा राशि जमा करने के बाद)
87	आवास उपलब्ध कराने के लिए लाइसेंस जारी करना/नवीनीकरण
88	मांस की बिक्री के लिए लाइसेंस जारी करना/नवीनीकरण
89	औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत ब्लड बैंक के संचालन के लिए लाइसेंस जारी/नवीनीकरण। (1940 का केंद्रीय अधिनियम 23)
90	डीलर का लाइसेंस जारी करना/नवीनीकरण
91	निर्माता का लाइसेंस जारी करना/नवीनीकरण
92	विस्फोटक नियम, 2008 के तहत दुकान से पटाखों के कब्जे और बिक्री के लिए एनओसी जारी करना/नवीनीकरण करना
93	अधिभोग प्रमाणपत्र जारी करना /नवीनीकरण
94	औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (केंद्रीय अधिनियम 23, 1940) और फार्मसी अधिनियम, 1948 (केंद्रीय अधिनियम 8, 1948) के तहत अस्पताल में दवा की दुकान (आउटडोर और इनडोर फार्मसी दोनों) संचालित करने के लिए पंजीकरण जारी करना/नवीनीकरण करना।
95	खुदरा औषधि लाइसेंस (फार्मसी) जारी करना /नवीनीकरण
96	ट्रेड लाइसेंस प्रमाणपत्र जारी करना /नवीनीकरण
97	थोक औषधि लाइसेंस जारी करना /नवीनीकरण
98	पर्यटक परमिट/पास जारी करना
99	रोजगार इच्छुकों का पंजीकरण (जी2सी)
100	गैर-परिवहन वाहन के लिए लर्नर लाइसेंस
101	परिवहन वाहन के लिए लर्नर लाइसेंस
102	पुस्तकालय सदस्यता
103	लोड परिवर्तन/श्रेणी परिवर्तन (जी2बी)
104	गुमशुदा व्यक्ति पंजीकरण (जी2सी)
105	राजस्व अभिलेखों का उत्परिवर्तन (जी2सी)
106	बीपीएल परिवारों के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
107	नया बिजली कनेक्शन (व्यवसाय) (जी2बी)
108	मेलों/मेलों/प्रदर्शनी/खेल आयोजनों आदि के लिए एनओसी
109	शस्त्र विक्रेताओं के लाइसेंस जारी/नवीनीकरण हेतु एनओसी
110	पूर्व स्वामित्व वाले वाहनों के लिए एनओसी
111	स्कूलों के लिए एनओसी (जी2बी)
112	विस्फोटक नियम, 2008 के तहत भंडारगृह में पटाखों के भंडारण के लिए एनओसी
113	पेट्रोलियम नियम, 2002 के तहत पेट्रोल के आयात और भंडारण के लाइसेंस के लिए एनओसी
114	लाउड स्पीकर के उपयोग के लिए एनओसी (केवल उस स्थिति में लागू होगा जब एसडीएम अनुमति देने से पहले संबंधित थानेदार से एनओसी प्राप्त कर लें)
115	राज्य के बाहर जाने वाले वाहनों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी)
116	दूसरे राज्यों में वाहनों के स्थानांतरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी)।
117	वृद्धावस्था भत्ता
118	पुलिस में ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण (जी2सी)
119	ऑनलाइन एफआईआर पंजीकरण/एफआईआर की प्रति
120	सहकारी समितियों का ऑनलाइन पंजीकरण
121	ओपीडी अपॉइंटमेंट के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली (जी2सी)
122	पासपोर्ट सत्यापन
123	रोगी पंजीकरण (जी2सी)
124	सीवेज कनेक्शन के लिए अनुमति

125	संपत्ति के हस्तांतरण की अनुमति
126	जल कनेक्शन के लिए अनुमति (जी2सी)
127	ईट भट्टा (गैड एवं चिमनी) निर्माण की अनुमति (आवेदन प्राप्ति के बाद)
128	पुलिस क्लीयरेंस प्रमाण पत्र
129	गर्भवती महिला सहायता (लाभ हस्तांतरण सहित) (जी2सी)
130	निजी सुरक्षा एजेंसी सत्यापन
131	जुलूस/विरोध/हड़ताल अनुरोध
132	संपत्ति कर ऑनलाइन भुगतान (जी2सी)
133	राशन कार्ड डेटा सुधार और घरेलू मुखिया संशोधन
134	अधिकारों का रिकॉर्ड (आरओआर) (जी2सी)
135	पंजीकरण और लाइसेंसिंग - मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम (जी2बी)
136	विदेशियों का पंजीकरण (आगमन और प्रस्थान)
137	डीलर के माध्यम से पूर्णतः निर्मित परिवहन वाहनों का पंजीकरण
138	डीलर के माध्यम से गैर-परिवहन वाहनों का पंजीकरण
139	साझेदारी फर्म अधिनियम (जी2बी) के तहत साझेदारी फर्मों का पंजीकरण
140	सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (जी2बी) के तहत सोसायटी का पंजीकरण
141	पर्यटन सेवा प्रदाता का पंजीकरण/मान्यता/नवीनीकरण
142	बैटरी (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2016 के तहत पंजीकरण (संशोधित)
143	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत पंजीकरण
144	गलियों/सड़कों से ठोस अपशिष्ट हटाना
145	शस्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण (यदि लाइसेंस समाप्ति तिथि से पहले प्रस्तुत किया गया है और लाइसेंस जारी करने वाला जिला वही है जहां सेवा मांगी गई है)
146	स्ट्रीट लाइटों को बदलना
147	स्कूल पंजीकरण (जी2बी)
148	बीज प्रदायगी
149	उचित मूल्य दुकान लाइसेंस का समर्पण
150	किरायेदार सत्यापन (यदि स्थानीय क्षेत्र का निवासी हो)
151	राज्य के भीतर खरीदे गए पुराने वाहनों के स्वामित्व का हस्तांतरण
152	मृत्यु के मामले में संपत्ति का हस्तांतरण (निर्विरोध)
153	बिक्री के मामले में संपत्ति का स्थानांतरण
154	विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन

किसी भी सुझाव के लिए कृपया अधोहस्ताक्षरी से संपर्क करें:

श्रीमती सरिता तनेजा

उप सचिव

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

5वीं मंजिल, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली

संपर्क नंबर: 011-23401457

ईमेल आईडी: sarita.taneja@nic.in



सत्यमेव जयते

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
भारत सरकार